Publication Name: The Pioneer
Publication Date: 04/02/2026
Edition: Delhi
Page No: 9
CCM: 43.9

Clarity in policy is necessary to empower drivers

ड्राइवरों को सशक्त बनाने के लिए नीति में स्पष्टता जरूरी

नई दिल्ली। ड्राइवरों के स्वामित्व वाले और सब्सक्रिप्शन आधारित राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी की शुरूआत भारत की बदलती गिग इकोनॉमी में एक अहम कदम है। यह प्लेटफॉर्म पारंपरिक एग्रीगेटर कंपनियों के मुकाबले कम कमीशन और सहकारी मॉडल पर काम करता है, जिसका मकसद ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को उनकी कमाई और काम पर दोबारा नियंत्रण देना है लेकिन जैसे-जैसे यह मॉडल आगे बढ़ रहा है, एक बुनियादी नीतिगत सवाल और गहरा होता जा रहा है। क्या भारत की टैक्स व्यवस्था ड्राइवरों को सशक्त बनाने वाले ऐसे नवाचारों का साथ देगी, या अनजाने में उन्हें नुकसान पहुंचाएगी ?इस बहस के केंद्र में है सब्सक्रिप्शन या रंर (सॉफ्टवेयर-एज-ए-सर्विस) मॉडल पर चलने वाले राइड प्लेटफॉर्म्स पर प्रस्तावित 5 प्रतिशत जीएसटी। पारंपरिक प्लेटफॉर्म हर राइड पर कमीशन काटते हैं, जबकि रंर मॉडल अलग है। इसमें ड्राइवर एक तय सदस्यता शुल्क देकर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं।

Publication Name: Navodaya Times
Publication Date: 04/02/2026
Edition: Delhi
Page No: 14
CCM: 93.67

Online Portal for Cooperative Lokpal: Shah

सहकारी लोकपाल के लिए होगा ऑनलाइन पोर्टल : शाह

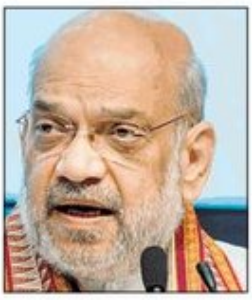

नई दिल्ली, 3 फरवरी (एजेंसी) सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि सरकार शिकायतों और अपीलों का पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-आधारित प्रबंधन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 'सहकारी लोकपाल' के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार कर रही है।

शाह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि बहुराज्यीय सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 में संशोधन के बाद 5 मार्च 2024 को सहकारी लोकपाल की नियुक्ति की गई थी। सहकारी लोकपाल बहुराज्यीय सहकारी समितियों के सदस्यों द्वारा उनकी जमा राशि, समिति के कामकाज या व्यक्तिगत अधिकारों को प्रभावित करने वाले किसी अन्य मुद्दे से संबंधित शिकायतों की जांच करता है। शाह ने कहा कि सरकार ने सहकारी लोकपाल के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार करने की पहल की है, जो शिकायतों और अपीलों के पारदर्शी, कुशल और प्रौद्योगिकी-आधारित प्रबंधन के लिए किया जा रहा है। सहकारी लोकपाल सहकारी सूचना अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध किसी भी सदस्य द्वारा दायर अपील के लिए अपीलीय प्राधिकार भी है।